

भूख से मुक्ति का राष्ट्रीय संकल्प है अटल कैटीन योजना



–ललित गर्ग

और मानवीय सोच के साथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुरू की गई रुपये 5 में भोजन उपलब्ध कराने की ह्राअटल कैटीन योजना निस्संदेह एक दूरदर्शी, करुणामय, मानवीय और जनकल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और मानवीय है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राजधानी जैसे महानगर में, जहाँ एक ओर समृद्धि और चमक-दमक है, वहीं दूसरी ओर असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शाचालक, ठेला-पटरी वाले, घरेलू कामगार और बेघर लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इनके लिए दो वक्त का सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन आज भी एक चुनौती बना हुआ है। अटल कैटीन योजना इन्हीं वर्गों के लिए आजगरीबेनाकर सामने आई है, जो संकल्प से सिद्धि के लक्ष्य को दशातां है और इसे देश में भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।



इस योजना का शुभारंभ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर किया जाना केवल एक औपचारिक तिथि चयन नहीं, बल्कि एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक है। अटलजी का संपूर्ण राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन अंत्योदय अर्थात् समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचार से प्रेरित रहा। वर्ष 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अटलजी के लिए और गरीबों केवल अन्नदान नहीं, बल्कि नीति का केंद्र था। उस योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती दूरी पर अनाज उपलब्ध कराया गया, जिससे करोड़ों लोगों को भुखमरी से राहत मिली। अटल कैटीन योजना उसी सोच का आधुनिक शहरी संस्करण है, जहाँ अनाज के बजाय तैयार, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन सिधे थाली में परोसा जा रहा है। यह नीतिगत निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि सुशासन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील क्रियान्वयन से साकार होता है। अटल कैटीन में भोजन की कीमत रुपये 5 रखी गई है, जबकि सरकार प्रत्येक थाली पर रुपये 25 की सब्सिडी दे रही है। यह मूल्य निर्धारण अत्यंत सोच-समझकर किया गया है। भोजन पूरी तरह मुफ्त न देकर एक न्यूनतम राशि तय करने का उद्देश्य यह है कि भोजन की कद्र बनी रहे और लाभार्थी इसे भीख नहीं, बल्कि अधिकार और सम्मान के रूप में ग्रहण करें। यह नीति सामाजिक मनोविज्ञान को समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

रेखा गुप्ता सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए जिस संवेदनशीलता, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है, वह उनके प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व को रेखांकित करता है; अटल कैटीन उसी योजनाएँ बनाती हैं कि वे शासन की सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम मानती हैं। किंतु सदी के इस कठोर मौसम में दिल्ली की सड़कों, फुटपाथों और फ्लाईओवरों के नीचे टिटुरती रातें काटने को विवश गरीब और बेघर लोगों के लिए केवल मौसमी रैन-बसरे पर्याप्त नहीं हैं, आवश्यकता एक स्थायी, स्मरन्वित और मानवीय शौरी-रक्षा योजना की है, जिसमें अस्थायी आश्रय के साथ गरम वस्त्र, पौष्टिक भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था हो, ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की सड़कों पर कोई भी व्यक्ति संदे रात में बेसहारा और अश्वय न रहे; ऐसा कदम न केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता का प्रमाण होगा, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी का भी सशक्त निर्वाह बनेगा।महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उपलब्ध कराया जा रहा भोजन पोषण मानकों के अनुरूप है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई मानकों का पालन किया जाता है, जिसमें प्रति थाली 700-800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है। डिजिटल टोकन, सीसीटीवी और निगरानी के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक कैटीन प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता रखी है, और 100 कैटीन खोलने का लक्ष्य है। दाल, सब्जी, रोटी/चावल जैसे संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आरओ वाटर एवं अचार आदि भी परोसा जा रहा है ताकि यह योजना केवल पेट भरने तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य सुधार में भी योगदान दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और निम्न आय वर्ग के लिए मुफ्त एवं रियायती अनाज योजनाएँ लगातार संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलों ने संकट काल में करोड़ों परिवारों को राहत दी है।इन योजनाओं का मूल दर्शन यही है कि भूखा नागरिक न आत्मनिर्भर बन सकता है और न ही राष्ट्रनिर्माण में भागीदार। रेखा गुप्ता सरकार की अटल कैटीन योजना इन राष्ट्रीय प्रयासों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। यह दशाती है कि केंद्र और राज्य, यदि समान मानवीय दृष्टि से काम करें, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से संभव है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भुखमरी और अपराध के बीच गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो वह व्यवस्था के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण अपनाने लगता है। यही कारण है कि अनेक महान नेताओं ने यह कहा है कि गरीब को पहले रोटी दो, उपदेश बाद में।

भूख को खिलाना किसी प्रकार का राजनीतिक प्रलोभन नहीं है। यह सच्ची राष्ट्रभक्ति, मानवीय कर्तव्य और सामाजिक सुरक्षा का आधार है। अटल कैटीन जैसी योजनाएँ अपराध को निश्र्चित करने, सामाजिक असंतोष को कम करने और लोकतंत्र को निश्वास को मजबूत करने का कार्य करती हैं। हालाँकि, किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता केवल उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि उसके पारदर्शी, निगरानी और ईमानदार क्रियान्वयन से तय होती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि अटल कैटीन योजना को भ्रष्टाचार, अव्यय्य और लापरवाही से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। खाद्य सामग्री को खरीद, भोजन की गुणवत्ता, लाभार्थियों की पहुँच, वित्तीय प्रबंधन और संचालन व्यवस्था-हर स्तर पर सख्त निगरानी, नियमित ऑडिट और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि इस योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रवेश करता है, तो वह न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, बल्कि गरीब के विश्वास के साथ भी विश्वासघात होगा।

दिल्ली की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है। शहरीकरण के इस दौर में लगभग हर बड़े शहर में श्रमिक और निम्न आय वर्ग भोजन संकट से जूझ रहा है। यदि प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऐसी योजनाएँ विकसित करे, तो देश से भुखमरी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि ऐसी योजनाएँ खर्च नहीं, बल्कि सामाजिक निवेश हैं। यह निवेश समाज को स्थिरता, शांति और विश्वास लाौताता है। अंततः रुपये 5 की थाली केवल भोजन नहीं है। यह करुणा, गरिमा और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्योदय सोच और नरेंद्र मोदी के वर्तमान नेतृत्व की मानवीय दृष्टि का सार्थक संमेल है। रेखा गुप्ता सरकार की यह पहल यह संदेश देती है कि सुशासन वही है, जो सबसे पहले सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुँचे। यदि इस योजना को पारदर्शिता, ईमानदारी और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के लिए भूख-मुक्त भारत की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।

वैश्विक विश्व युद्ध के मुहानें पर बैठी मानवता



संजीव ठाकुर

सावधान? मानवीय जीवन आज परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ा है और पूरी पृथ्वी जैसे किसी सक्रिय ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि अगला सनकी आदेश किस राजधानी से निकलेगा। परमाणु संपन्न देशों के शासक स्वयं की वैश्विक सिरमौर सिद्ध करने की खतरनाक होड़ में अपनी

राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, विस्तारवादी मंसूबों और व्यक्तिगत सनकों को मानवता के अस्तित्व से ऊपर रख चुके हैं।

चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश जहाँ परमाणु शक्ति तानाशाही प्रवृत्तियों के हाथों में केंद्रित है। वहाँ यह खतरा और भी भयावह हो जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब सत्ता विवेक से कट जाती है तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम आज भी मानवता के माथे पर कलंक की तरह दर्ज हैं। उसे समय के परमाणु हमले के विकिरण के दुष्प्रभाव आज भी जापान के बच्चों के शरीर और भविष्य में देखे जा सकते हैं।

उत्तर कोरिया के शासक किम

जोंग उन द्वारा 2022 के बाद से सौ से अधिक हथियारों के परीक्षण जिनमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को लक्ष्य करने वाली परमाणु मिसाइलें शामिल हैं। यही इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि यह देश किसी भी क्षण सनक में विनाशकारी कदम उठा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते बल्कि वैश्विक संतुलन को झकझोर कर रखा देते हैं और यूक्रेन को नाटो तथा अमेरिका से मिल रही सहायता के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दे चुके हैं। जबकि उन्हें यह अनुमान ही नहीं था कि यूक्रेन इतना लंबा प्रतिरोध कर पाएगा, चीन और

ताइवान विवाद में भी अमेरिका के परोक्ष हस्तक्षेप से नाराज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र युद्ध के केंद्र में आ सकता है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक विरोधी बन चुके हैं और अमेरिका स्वयं को विश्व का सर्वशक्तिमान बनाए रखने के दबाव में लगातार युद्धोन्मुखी नीति अपनाए हुए है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया की सीमा पर लगातार सैन्य अभ्यास को व्योंगयांग हमले के पूर्वाभ्यास के रूप में देख रहा है जबकि अमेरिका, जापान

हिंदी:भारत की आत्मा से विश्व मंच तक भाषा



वैश्विक स्तर पर भारत की सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषाई, सांस्कृतिक और वैचारिक विविधता में निहित है।विश्व के किसी भी देश में इतनी भाषाएँ, बोलियाँ परंपराएँ व सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ एक साथ सह- अस्तित्व में नहीं पाई जातीं। इस विविधता के महासागर में यदि कोई एक सूत्र है, जो भारत को भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तरपर जोड़ता है, तो वह है हिंदी भाषा। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं,बल्कि भारत की सामूहिक चेतना,स्मृति और संस्कृति की संवाहक है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी मोदिद्या महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि हिंदी: केवल भाषा नहीं, भावनात्मक सेतु हैं,हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है परंतु इसकी शक्ति केवल संख्या में नहीं,बल्कि संवेदना, आत्मीयता और भावाभिव्यक्ति में निहित है। हिंदी वह भाषा है, जिसमें प्रेम भी सरल है, पीड़ा भी सहज है और प्रतिरोध भी स्वाभाविक।जहाँ कई भाषाएँ औपचारिक संवाद तक सीमित रहती हैं, वहीं हिंदी व्यक्ति के हृदय से सिधे संवाद करती है। यही कारण है कि ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक और राजनीति से लेकर जनआंदोलनों तक हिंदी की भूमिका केंद्रीय बनी हुई है।इसी ऐतिहासिक

सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व के कारण हिंदी के सम्मान और प्रचार-प्रसार हेतु विशेष दिवस समर्पित किए गए हैं, 14 सितंबर (राष्ट्रीय हिंदी दिवस) और 10 जनवरी (विश्व हिंदी दिवस)।भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था।यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था,बल्कि यह उस ऐतिहासिक संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसने औपनिवेशिक शासन की भाषाई विरासत से बाहर निकलकर भारतीय भाषाओं को केंद्र में लाने का प्रयास किया।वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है,जिसका उद्देश्य हिंदी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाना, वैश्विक संवाद की भाषा के रूप में स्थापित करना और यह दर्शाना है कि हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं,बल्कि एक वैश्विक भाषा बन चुकी है।यह दिवस भारत की सांप्रत पावर, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण आधार है।

साथियों बात अगर हम डिजिटल युग में हिंदी: विरासत से भविष्य की तकनीक तक इसको समझने की करें तोआज का युग डिजिटल क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और वैश्विक संचार का युग है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि तकनीक केवल अंग्रेजी या कुछ चुनिंदा भाषाओं तक सीमित रहेगी, लेकिन हिंदी ने इस धारणा को तोड़ दिया है।आज हिंदी:सोशल मीडिया की सबसे सक्रिय भाषाओं में से एक है,डिजिटल समाचार, ब्लॉग, पॉडकास्ट और यूट्यूब कंटेंट की प्रमुख भाषा बन चुकी है। एआई

आधारित अनुवाद वॉइस असिस्टेंट और चैटबॉट में तेजी से अपनाई जा रही है।हिंदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह पारंपरिक ज्ञान से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक समान रूप से सक्षम है। यही कारण है कि विश्व हिंदी दिवस का एक प्रमुख उद्देश्य डिजिटल युग में हिंदी की प्रासंगिकता और क्षमता को रेखांकित करना है।

साथियों बात अगर हम अंग्रेजी बनाम हिंदी : आजादी के 75 वर्ष बाद भी वैचारिक गुलामी? इसको समझने की करें तो 1947 में भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन आज भी एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ाहै, क्या हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र हो पाए हैं? विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है कि क्या आज भी अंग्रेजी बोलना सामाजिक प्रतिष्ठा और आधुनिकता का प्रतीक बना हुआ है? अज अनेक माता- पिता गर्व से यह दिखाना चाहते हैं कि उनका बच्चा कितनी धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलता है। छोटी उम्र से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना और हिंदी से दूरी बनाना कहीं न कहीं मानसिक उपनिवेशवाद का प्रतीक है। हमें अपनी भाषाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं,संतुलन की आवश्यकता हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विश्श अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के विरोध का नहीं, बल्कि हिंदी के आत्मसम्मान का है। अंग्रेजी वैश्विक संपर्क की भाषा है, परंतु हिंदी हमारी पहचान की भाषा है।यदि हम बच्चों को केवल अंग्रेजी में सोचने और समने देखने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, तो वे अपनी जड़ों से कटते चले जाएंगे। समय आ गया है कि: हिंदी को शिक्षा, तकनीक और प्रशासन में समान महत्व दिया जाए,बच्चों को

हिंदी बोलने, लिखने और सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।हिंदी को कमतर समझने की मानसिकता को समाप्त किया जाए।भारत में लगभग 1500 से अधिक भाषाएँ और बोलियाँ हैं, जिनमें से अनेक विलुपित के कगार पर हैं। यह संकट केवल भाषाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। हिंदी का शक्तिकरण तभी सार्थक होगा, जब वह अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सह- अस्तित्व और सम्मान के सिद्धांत पर आगे बढ़े। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में सशक्त बनाते हुए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की भाषाई विविधता सुरक्षित रहे।

साथियों बात अगर हम हिंदी और वैश्विक पहचान: संयुक्त राष्ट्र की सातवीं भाषा की ओर इसको समझने की करें तो, भारत सरकार लंबे समय से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की सातवीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएँ हैं –अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी। हिंदी के पक्ष में तर्क अत्यंत मजबूत हैं: यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है।।भारत वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और शांति मिशनों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हिंदी अनेक देशों में पढ़ाई और शोध की भाषा बन चुकी है। यदि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता है, तो यह केवल भाषा की जीत नहीं, बल्कि वैश्विक बहुभाषिक लोकतंत्र की जीत होगी।

साथियों बात अगर हम वर्ष में दो बार हिंदी दिवस मनाने के इतिहास को समझें की करें तो, हिंदी के वैश्विक शिकार की नींव 10

जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में पड़ी। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदी भारत की सीमाओं से बाहर भी जीवंत, प्रासंगिक और प्रभावशाली भाषा है।इसके बाद हिंदी का वैश्विक आंदोलन और तेज हुआ। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को औपचारिक रूप से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से लेकर आज तक भारत के सभी दूतावासों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों विभवविद्यालयों और प्रवासी भारतीय समुदायों में यह दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है।

साथियों बात अगर हम संवैधानिक वैचारिक डिजिटल और तकनीकी दृष्टिकोण से हिंदी भाषा की स्थिति को समझने की करें तो,संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना केवल एक प्रशासनिक निर्णयनहीं था बल्कि यह औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और राष्ट्रीय अस्मिता की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को संरक्षण और संवर्धन का दायित्व सौंपा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा केवल संरक्षण का साधन नहीं,बल्कि लोकतंत्र, समानता और जनभागीदारी की रीढ़ है। स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी यदि हिंदी को बोलना या अपनाना हीनता से जोड़ा जाए, तो यह वैचारिक गुलामी का संकेत है। सच्ची स्वतंत्रता तभी पूर्ण

आंख मूंदकर खड़े रहते हैं।भारत की स्थिति इन परिस्थितियों में अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि एक ओर उसकी की बूमिका निभाने का प्रयास करती रह। है। परंतु जब विश्व की प्रमुख शक्तियां ही संवाद की बजाय दंभ और हथियारों की भाषा बोलने लगें तो किसी भी क्षण चिंगारी विश्वयुद्ध में बदल सकती है और यदि ऐसा हुआ तो यह युद्ध केवल देशों का नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता और पृथ्वी के अस्तित्व का युद् होगा, ऐसे समय में विश्व को नेताओं का नेतृत्व अपनी वैश्विक बादशाहत बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार दिखाई देता है और उसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल जैसे देश

होगी जब शासन, शिक्षा और समाज में हिंदी को सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया जाए।डिजिटल युग में हिंदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल साहित्य या परंपरा की भाषा नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक की भी सक्षम भाषा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, वॉइस असिस्टेंट, ऑटो-ट्रांसलेशन सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता में हिंदी की उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है। आज करोड़ों लोग इंटरनेट पर हिंदी में खोज करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और संवाद स्थापित करते हैं, जिससे डिजिटल समावेशन संभव हो रहा है। विश्व हिंदी दिवस का मूल उद्देश्य यही है कि हिंदी को तकनीक- विरोधी नहीं, बल्कि तकनीक-सहयोगी भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सशक्त सेतु बन सके।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हिंदी का भविष्य हमारी जिम्मेदारी हैं हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मसंधन और संकल्प के अवसर हैं। हिंदी का भविष्य किसी सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना और व्यवहार से तय होगा। यदि हम: हिंदी में सोचें, हिंदी में गर्व महसूस करें हिंदी को आधुनिक, तकनीकी और वैश्विक बनाएं तो हिंदी न केवल भारत की आत्मा बनी रहेगी, बल्कि विश्व संवाद की सशक्त भाषा के रूप में भी स्थापित होगी। हिंदी केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना है। आइए, हिंदी को सम्मान नहीं, अधिकार दें।

ट्रम्प का वेनेजुएला कांड, भारत के लिए

भारत और वेनेजुएला एक-दूसरे से बहुत अलग देश हैं। दोनों के बीच भौगोलिक दूरी लगभग 14,250 किलोमीटर है। काराकस, दक्षिण अमरीका की कभी जीवंत मानी जाने वाली राजधानी, आज वैश्विक घटनाक्रम के केंद्र में है। वहां जो कुछ अचानक और चौंकाने वाला हुआ, वह केवल वेनेजुएला की कहानी नहीं, बल्कि उसमें भारत और शेष विश्व के लिए गंभीर सबक छिपे हुए हैं।

पहला सबक-- लोकतंत्र, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय कानून और सुशासन जैसे चमकदार शब्द वैश्विक राजनीति में अक्सर खोखले साबित होते हैं। व्यवहार में असहजता और कड़वी सच्चाई को ढकने का औजार बन जाते हैं। भ्रष्ट और स्वार्थी नेतृत्व इन्हीं आदर्शवादी नारों की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाता है। बाद में नव-औपनिवेशिक ताकतें इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने

विस्तारवादी आ?थक और राजनीतिक हितों को साधने का उपक्रम बनाती हैं। वेनेजुएला पर अमरीका का औचक सैन्य हमला उसी शाश्वत सिद्धांत को पुनर्स्थापित करता है, जो सदियों से वैश्विक राजनीति को संचालित करता आया है-जिसकी लाठी, उसकी भैंस। दूसरा-गरीबी मिटाने और समृद्धि लाने का कोई लघु-मार्ग नहीं होता। इसके लिए प्रतिस्पर्धा, कठोर परिश्रम और उत्पादन-आधारित अर्थव्यवस्था अनिवार्य है।

नौ नीतियां संपत्ति सृजन करने की बजाय केवल संपत्ति पुनरवतरण को प्राथमिकता दें, वे अंततः देशों को आर्थिक तबाही और राजनीतिक पराधीनता की ओर ले जाती हैं। उत्पादन की उपेक्षा करके केवल पुनरवतरण करना इसलिए भी खतरनाक है, क्योंकि वह वास्तविक लोकतंत्र को धीरे-धीरे, कानूनी रास्तों से,

के रक्त का बहाव यथावत रखता है। वह शरीर के अतिरिक्त विषैले तत्व बाहर निकालने में सहायक होता है। यह शरीर के ताप को ठीक बनाए रखता है। यह रंगहीन पीने का पानी निश्चय ही साफ होना चाहिये, शुद्ध स्वच्छ गंधहीन और गंदगी रहित होना चाहिये। इसमें किसी तरह के हानिकारक तत्व नहीं होना चाहिये।

पीने का पानी कैसा हो? इस विषय पर वैज्ञानिकों ने काफी प्रयोग किये हैं और पानी की गुणवत्ता को तय करने के मापदंड बनाये हैं। पीने के पानी का रंग, गंध, स्वाद सब अच्छा चाहिए। ज्यादा कैल्शियम या मैगनेशियम वाला पानी कठोर जल होता है और पीने के योग्य नहीं होता है। पानी में उपस्थित रहने वाले हानिकारक रसायनों की

मात्रा पर भी अंकुश आवश्यक है। आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी तथा फ्लोराईड, नाइट्रेट आदि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। पानी में कुल कठोरता 300 मिली ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होने पर पानी शरीर के लिये नुकसानदायक हो जाता है। पानी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणुओं का होना, हानिकारक रसायनों का होना कठोरता होना पानी को पीने के अयोग्य बनाता है।

पीने का जल शुद्ध हो, प्यास बुझाये, मन को प्रफुल्लित रखे, तभी वह शुद्ध प्रेम जल होता है। हमारे शरीर का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना है। प्रतिदिन शरीर को 6 से 10 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता का एक मात्र पर भी अंकुश आवश्यक है। आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी तथा फ्लोराईड, नाइट्रेट आदि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। पानी में कुल कठोरता 300 मिली ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होने पर पानी शरीर के लिये नुकसानदायक हो जाता है। पानी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणुओं का होना, हानिकारक रसायनों का होना कठोरता होना पानी को पीने के अयोग्य बनाता है।

पीने का जल शुद्ध हो, प्यास बुझाये, मन को प्रफुल्लित रखे, तभी वह शुद्ध प्रेम जल होता है। हमारे शरीर का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना है। प्रतिदिन शरीर को 6 से 10 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता का एक मात्र पर भी अंकुश आवश्यक है। आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी तथा फ्लोराईड, नाइट्रेट आदि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। पानी में कुल कठोरता 300 मिली ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होने पर पानी शरीर के लिये नुकसानदायक हो जाता है। पानी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणुओं का होना, हानिकारक रसायनों का होना कठोरता होना पानी को पीने के अयोग्य बनाता है।

सभी संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और शक्ति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चौथा सबक-सभी देशों में ऐसे नेता होते हैं, जो सत्ता की धोखे में जनता को असंभव सपने दिखाते हैं और उनकी भावनाओं से खेलकर सत्ता में आ जाते हैं। कुर्सी मिलने के बाद वे अव्यवहारिक वादे पूरे नहीं कर पाते, जिससे धीरे-धीरे या अचानक, निर्दयी तानाशाह में बदल जाते हैं। वेनेजुएला ऐसे ही नेताओं का शिकार रहा है, जिनकी सनकी नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत भी एक समय इसका शिकार रहा था। 1969 में कांग्रेस के विभाजन पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, पूरे विश्व की पूंजीपतियों का एजेंट बताकर भारी बहुमत से जीत हासिल की।

उनकी नीतियां उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की बजाय पुनर्वितरणऔर

बड़ा भाग खाद्य पदार्थों के रूप में शरीर ग्रहण करता है। शेष पानी मनुष्य पीता है। गर्मियों में पानी ज्यादा चाहिये क्योंकि पसीने के रूप में काफी ज्यादा पानी शरीर से वापस बाहर निकल जाता है, सर्दी में पानी की मात्रा कम चाहिये। पानी भोजन के पाचन, रूधिर संचरण तथा समस्त अन्य जैव क्रियाओं के लिये अत्यंत आवश्यक है। सुबह उठकर एक गिलास शीतल जल का सेवन व्यक्ति को कई बीमारियों से बचाता है।

हमारे यहां अमूलतः पर पानी की शुद्धता और स्वच्छता के बारे में बहुत लापरवाही बरती जाती है। बर्तन लायक साफ पानी न तो उपलब्ध है और न ही इसकी मांग की जाती है। पानी में तरह तरह की गंदगी होती है,

राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित रही। इसका नतीजा यह हुआ कि कालांतर में दूध, वनस्पति घी, गेहूं, चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई और कालाबाजारी बढ़ गई। उसी आ?थक अव्यवस्था ने व्यापक जन-असंतोष को जन्म दिया। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिराजी का चुनाव रद्द कर दिया। इस पर उन्होंने देश पर आपातकाल थोप दिया, जो मार्च 1977 तक जारी रहा। लातिन अमरीकी देश वेनेजुएला का पतन न तो प्रतिबंधों से शुरू हुआ और न ही ट्रम्प की सनक से। इसकी जड़ें उस आकर्षक, लेकिन घातक विचार में मिलती हैं, जिसमें मान्यता थी कि केवल पुन?वतरण ही उत्पादन का विकल्प हो सकता है। 1999-2013 तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो शावेज ने खुद को मसीहा के रूप में पेश किया। उनका तर्क था कि तेल से होने वाली आय सिर्फ जनता की है,

जिसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। सच पृष्ठित तो इसके बारे में आम लोगों को अधिक जानकारी थी नहीं है। गंदगी में जो रोगों के जीवाणु होते हैं, वे आँख से दिखते नहीं, केवल माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इसी गंदगी की वजह से और इसके रोग के जीवाणुओं से बहुत सी बीमारियां होती है जैसे दस्त, पेचिस, हैजा, पोलियो, नारू और भी कई। आंत संबंधी रोग पानी से होने वाली बीमारियों के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादातर लोग पीने का पानी किसी पोखर या तालाब से लेते हैं जहां बर्तन भी धोए जाते हैं, कपड़े भी धोए जाते हैं, लोग खुद भी नहाते हैं, गाय, भैंसों को भी नहलाते हैं। यह सारी गंदगी अन्दर चली जाती है। इसी प्रकार पानी कुओं से भी लिया जाता

न कि निजी कंपनियों या वैश्विक रणनीतिक साझेदारों की। देखते ही देखते हजारों से अधिक निजी कंपनियां जन्म कर ली गईं। अत्यधिक मुद्राएं छापी गईं, जिससे बेतराशा महंगाई बढ़ी। पूर्ति गई और भुखमरी बढ़ गई।

पिछले कुछ समय से कांग्रेस के शीर्ष नेता और वर्तमान लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुनरवतरण की मांग को भारत में तेज कर रहे हैं, जिसमें अक्सर पिताकाया आबादी, उतना हक नामक जुमला छोड़ा जाता है। सफल देश विभिन्न योजनाओं से मुनाफे का पुनरवतरण करते हैं। इंदिराजी और चावजे ने पुनरवतरण के नाम पर आय के स्रोत को नष्ट कर दिया था। राहुल भी सत्ता के लिए इसे दोहराना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में वेनेजुएला एक चेतावनी है। जो देश लोकलुभावन वादों और पहचान-आधारित पुनरवतरण के जाल में फंसते हैं, वे अंततः पतन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। -बलबीर पुंज

है जो ज्यादा गहरे नहीं होते और खुले छोड़ दिए जाते हैं। हवा के साथ हमें धूल, मिट्टी, परे, पक्षी की बीट इत्यादि जाकर मिलती है और पानी को प्रदूषित करती है। कुछ गांवों में हैज़रंपं की सुविधाएं दी गई हैं, परंतु उसके ऊपर की गोलाई में कीचड़ व कूड़ा जमकर पड़ा होता है। वहां से गंदा पानी धीरे-धीरे जमीन में रिसकर स्वच्छ पानी को खूबाय कर देता है। फिर वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। पाइप लाइनों से आने वाले पानी में भी पाइप लाइन की टूटपूट,जंग,सेवेज का पानी इन पाइप लाइनों में मिलने और पानी इन पाइप लाइनों के अभाव में पानी दूषित हो जाता है और जान लेवा साबित होता है।(अंजनी सक्सेना-विभूति फीचर्स)



जन्म जन्म, कबूतरां बुनागत, आ हर संभव स्थाल रखे यी-उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने साल 2015 से 2025 तक अपनी पत्नी को पढ़ाई-लिखाई और घर का सारा खर्च अकेले उठाया। धर्मरे के अनुसार, उनकी पत्नी पिछले छह महीनों से गायब थी, लेकिन एक महीने पहले उन्हें पता चला कि वह दिनेश वर्मा (पुत्र राजेंद्र वर्मा, निवासी सिरिया गांव) के साथ भाग गई है और संभवतः दूसरी शादी कर ली है। पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी अपने साथ उनके छोटे बेटे, अयाना, को भी ले गई है। धर्मरे को डर है कि उनके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और वे अपने बच्चे को धमकियां दे रहे हैं। धर्मरे ने वॉट्सएप पर साक्षात्कार किया कि उनकी एक भतीजी और दामाद भी सिरिया गांव के पास रहते हैं, जिन्हें आरोपी फ्लाजेट डरा-धमक रहे हैं। उन्हें पता नहीं है और ब्रह्मसेवक फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को वापस चाहता हूँ। मुझे और मेरे परिवार को उन लोगों से खुद हार है, धर्मरे ने कहा। उन्होंने सरकार और स्थानीय पुलिस से मामले को गिम्पक्ष जांच करने और उनके बच्चे को सुरक्षित वापस दिलाने की अपील की है।